

## बीएसईएस के 40 लाख उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक बोनांजा

### समय पर बिल भुगतान करें, प्रतिमाह पूरे 300 रुपये का कैशबैक पाएं

- 31 मार्च तक की इस स्कीम में पूरे 1200 रुपये का कैशबैक मिल सकता है

नई दिल्ली: 18 जनवरी, 2018। बीएसईएस उपभोक्ता समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान कर प्रति बिल, प्रति माह, पूरे 300 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं। वैसे तो यह स्कीम जनवरी से मार्च माह तक के लिए है, लेकिन उपभोक्ता चाहें, तो वे अप्रैल के बिल पर भी कैशबैक ले सकते हैं। लेकिन, इसके लिए उन्हें अप्रैल माह के बिल का प्री-पेमेंट 31 मार्च के पहले करना होगा। इस तरह, चार महीनों के दौरान उन्हें पूरे 1200 रुपये का कैशबैक मिल सकता है।

बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने अपने 40 लाख उपभोक्ताओं के लिए यह स्कीम मोबीक्विक के साथ मिलकर शुरू की है। हर माह 300 रुपये का कैशबैक लेने के लिए, उपभोक्ता को मोबीक्विक की वेबसाइट या उसके मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

कैशबैक को कैसे रिडीम करें:

बिल भुगतान करने के बाद, उपभोक्ता को मोबीक्विक की ओर से, एसएमएस के माध्यम से एक कूपन मिलेगा। जनवरी माह का कूपन फरवरी में एसएमएस किया जाएगा और, फरवरी व मार्च माह का कूपन मार्च में ही एसएमएस कर दिया जाएगा। अप्रैल माह के लिए प्री-पेमेंट किए गए बिल का कूपन भी मार्च में ही मिल जाएगा। उपभोक्ताओं को ये कूपन 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच रिडीम करवाने होंगे। बता दें कि यह कैशबैक स्कीम 31 मार्च को खत्म हो रही है।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, यह हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम समय पर बिल का भुगतान करने वाले अपने उपभोक्ताओं को पुरस्कृत व प्रोत्साहित करें। मोबीक्विक के साथ हमारा यह नया ऑफर उस दिशा में एक बड़ा कदम है।

बीएसईएस के अनुसार, बीएसईएस उपभोक्ता, उपरोक्त के अलावा 4000 से अधिक लोकेशनों / माध्यमों से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। बीएसईएस उपभोक्ताओं के पास ड्रॉप बॉक्स, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑटो डेबिट, नेबरहुड ईजी बिल, मनी एन मोबाइल, ऑक्सीजन आउटलेअस, आईटीजेड कैश कार्ड्स, बिल पेमेंट किऑस्क्स, चेक इन मेल सुविधा और की कंज्यूमर्स बैंकों के माध्यम से आरटीजीएस / एनईएफटी आदि से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

---